Volume 1, Issue 2 July 2015 ISSN NO: 2454 - 2326

North Asian International Research Journal Consortium

North Asian International Journal Of Multidisciplinary

Chief Editor
Dr. Nisar Hussain Malik

Publisher
Dr. Bilal Ahmad Malik

Associate Editor
Dr.Nagendra Mani Trapathi

Honorary
Dr.Ashak Hussain Malik

Welcome to NAIRJC

ISSN NO: 2454 - 2326

North Asian International Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi, Urdu all research papers submitted to the journal will be double-blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in Universities, Research Institutes Government and Industry with research interest in the general subjects

Editorial Board

J.Anil Kumar
Head Geography University of Thirvanathpuram

Kiran Mishra
Dept. of Engligh,Ranchi University, Jharkhand

R.D. Sharma
Head Commerse & Management Jammu University

Manish Mishra
Dept. of Engg, United College. (ALD)

Tihar Pandit
Dept. of Environmental Science, University OF Kashmir.

Neelam Yaday
Head Management MAT.K.M Patel College Thakurlie, Mumbai University.

Ashiq Mallik
Head Pol-Science G.P, PG College (ALD) Kanpur University

Sanjuket Das
Head Economicsn Samplpur University

Somanath Reddy
Dept. of Social Work, Gulbrga University.

R.P. Pandday
Head Education Dr. C.V.Raman University

K.M Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Simnani
Dept. of Poltical Science, Govt. Degree College, University of Kashmir.

Nisar Hussain
Dept. of Mdicine A.I. Medical College (U.P)

Khagendra Nath Sethi
Head Dept. of History Sambalpur University.

B.S.A.U
Dept. of Commerce, Aruganbad

Rajpal Choudhary
Dept. Govt. Engg. College Bikaner (Raj)

Rayaz Ahmad
Dept. of Botany Govt. Degree College Shopian. Kashmir University

Ravi Kumar
Director, H.I.M.T, Allahabad

Ashok D. Waga
Dept. of Accountancy, B.B.N. College Thana

M.C.P. Singh
Head Information Technology Dr C.V. Rama University

Rama Singh
Dept. of Poltical Science A.K.D.C. Allahabad, Uni. of (ALD)

Address: - Ashak Hussain Malik House No. 221 Gangoo, Pulwama, Jammu and Kashmir, India - 192301, Cell: 09086405302, 09906662570, Ph. No: 01933-212815,
Email: nairjc5@gmail.com Website: www.nairjc.com

A Peer Reviewed Refereed Journal

Page No. 64-76

भारत कीसुरक्षा पर चीन का प्रभाव

Arvind Kumar

Research scholar Department of Defence and strategic studies Allahabad University

(Allahabad)

Introduction:

भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से दो हैं। चीन और भारत में बहुत कुछ समान है: लंबा इतिहास,प्राचीन सभ्यताएं, अनूठी संस्कृतियां, विशाल भूभाग, विशाल आबादी और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा, दोनों देशों के पास औपनिवेशिक अधीनता में अपने अनुभवका हिस्सा था, और दोनों ने अपने प्रारंभिक पोस्ट-मुक्ति दशकों को उस समय के पूंजीवाद विरोधी सोवियत मॉडल से प्रेरित नियोजित आर्थिक प्रणालियों के साथ प्रयोग करने में बिताया। बाद में, दोनों को लगभग एक साथ आगे बढ़ना था, मुक्त बाजार तंत्र की ताकतों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से संगठित करने और खोलने की दिशा में। इसके अलावा, एशियाई दिग्गजों के रूप में भारत और चीन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मामलों में अत्यधिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया है।भारत की चीन नीति को मित्रता, भावुकता, भय, वैराग्य, भंगुरता, इच्छाधारी सोच और जुड़ाव द्वारा चिह्नित किया गया है।दृष्टिकोणों का यह मिश्रण संबंधों की जटिलता, चीन की चुनौती के प्रबंधन में भारत की कठिनाइयों, चीनी शासन की प्रकृति, भारत पर चीन के रणनीतिक लाभ और हाल के वर्षों में चीन के बढ़ते उदय को दर्शाता है। माओने क्रांतिकारी हिंसा से चीन को, अहिंसक संघर्ष से भारत को अपने कब्जे में ले लिया। (एयू: वाक्य स्पष्ट नहीं है।अधूरालगताहै।) चीन के नेता साम्यवादी थे जब कि भारत के नेता लोकतांत्रिक सोच में पोषित थे।माका

चीन देश के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को सुलझाना चाहता था,गांधी और नेहरू ऐतिहासिक गलतियों को भूलना और माफ करना चाहते थे।एक देश में उग्रवादियों ने सत्ता हथिया ली थी, दूसरे में शांति वादियों ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता संभाली थी।दोनों देशों के राजनीतिक पथ और उनके ने तृत्व की प्रकृति इतनी अलग थी कि सोच और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को संभावित रूप से देखा जाना चाहिए था। 1949 के आखिरी दिनों को याद करें,जब भारत पहला गैर-कम्युनिस्ट राष्ट्र बनना चाहता था।माओ के शासन को पहचानने के लिए।सरदार पटेल,तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को ऐसा लगता है कि आपका इरादा चीन को मान्यता देना है ... मेरी अपनी भावना यह है कि हम लीड देकर कुछ भी हासिल करने के लिए खड़े नहीं हैं।'2 अब यह महसूस किया जाता है कि अतीत में चीन के माओवादी अधिग्रहण और भारत के लिए इसके निहितार्थों को न समझ कर बहुत दूर गामी रणनीतिक गलतियाँ की गई थीं।

भारतऔरचीन: शुरुआत :.

भारत और चीन ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए।गैर-समाजवादी देशों में भारत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला दूसरा देश था। 1954 में, चीनी प्रीमियरझोउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने यात्राओं का आदान-प्रदान किया और संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रसिद्ध पांच सिद्धांतों की शुरुआत की।समझौते की प्रस्तावना में पांच सिद्धांत शामिल हैं जो अगले कुछ वर्षों के लिए भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ बने।पंचशील समझौते ने पीपुल्सलिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा विश्व की छत पर चीनी सैन्य नियंत्रण का द्वार खोल दिया। इसने ने फा,यूपी, (एयू: कृपया विस्तार करें।) और लद्दाख में भारतीय सीमाओं की ओर जाने वाली सड़कों और हवाई पट्टियों के एक नेटवर्क के निर्माण में अनुवाद किया। लेकिन भारत को उसकी 'उदारता' का कभी फायदा नहीं हुआ. इसके विपरीत, इसने एक शांतिपूर्ण और मैत्री पूर्ण पड़ोसी तिब्बत को खो दिया।एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीन-भारतीय संबंधों के सबसे विस्तृत

अध्ययनों में से एक में, जॉन गार्वर एक ठोस मामला बनाते हैं कि भारत-चीन संबंध पिछले कुछ वर्षों में एक गहरी और स्थायी भू-राजनीतिक प्रति द्वंद्विता से आकार लेते रहे हैं।गार्वर के अनुसार,प्रतिद्वंद्विता की जड़ें हैं: 'दशकों लंबे,बहुस्तरीय,और दो राज्यों में अक्सर तीखे संघर्ष' भूमि और लोगों के साथ संबंध.

समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ: उनके आस पास और उनके बीच का बदलता परिदृश्य'। 3 इसके अलावा, आदर्शवादी पाँच सिद्धांतों का चीन द्वारा कभी भी अक्षर श:याभावना में पालन नहीं किया गया।जून 1954 में हुई संधि (एयू: किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे?) के मुश्किल से 3 महीने बाद भारतीय क्षेत्र में चीनी घुस पैठ शुरू हुई। अन्य समस्याओं में तिब्बत का मुद्दा प्रमुख है। यह कहा जा सकता है कि भारत द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने और भारत की धरती से दलाई लामा की किसी भी चीन विरोधी गतिविधि के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के साथ, यह मुद्दा चीन-भारतीय राज्य से लेकर राज्य संबंधों तक में नहीं आता है। हालाँकि, बीजिंग को दलाई लामा के संबंध में भारत की मंशा पर आपत्ति है।

भारत और चीन के बीच चिड़चिड़े:

भारत और चीन के रूप में भारत और चीन दोनों ही एशिया में फलती-फूलती अर्थव्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं लेकिन फिर भी समस्या क्षेत्रों की सूची में सीमा का मुद्दा सबसे पहले आता है। यह भारत और चीन दोनों के लिए सबसे संवेदन शील है क्यों कि यह प्रत्येक पक्ष के संबंध में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से निकटता से संबंधित है।इस संबंध में भारत में उद्धृत किए जा रहे उदाहरणों में माओका चीन की 'हथेली' (तिब्बत) और 'पांच अंगुलियों' (नेपाल, सिक्किम, भूटान, नेफा और लद्दाख) का वर्णन शामिल है; 1980 के दशक में प्रकाशित उनके नक्शों और एटलस श्रृंखला के माध्यम से व्यक्त किए गए क्षेत्रों के 'ऐतिहासिक नुकसान' की पी आर सी (एयू: कृपया विस्तार करें।) की भावना के लिए भारत में भी संदर्भ दिए जा रहे हैं।ऐसे नक्शों को यह दावा करते हुए भी देखा गया था कि भारत का असम, यहां तक कि अंडमान'भी 'ऐतिहासिक रूप से' चीन का हिस्सा था।चीन का दावा उसके ऐतिहासिक रुख पर आधारित है कि भारत सहित उसकी सभी सीमा एंकिंग राजवंश काल के दौरान परिभाषित हैं, जो समाप्त हो गया था। 1912 में। भारत के साथ सीमा समस्या की जड़बीजिंग की स्थिति में निहित है कि उसके क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा,विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में 90,000 वर्ग किमी क्षेत्र, 1914 के शिमला सम्मेलन के बाद अवैध रूप से ब्रिटिश भारत द्वारा ले लिया गया था और वह भारत ब्रिटिश विरासत विरासत में मिली। इसने बीजिंग को मैक मोहन रेखा को अस्वीकार करने, सम्मेलन के एक उत्पाद और पूरे अरुणाचल प्रदेश (भारत के राज्य) को चीनी क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करने के लिए तर्क प्रदान किया है, जिसे 'दक्षिणीतिब्बत' कहा जाता है। चीन में आधिकारिक विद्वानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजिंग मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दे सकता है; यदि उसने ऐसा किया, तो यह 1962 के संघर्ष को 'आक्रामकता के युद्ध' के रूप में चीन की स्वीकारोक्ति होगी।

साथ ही एक अंतर्निहित स्वीकृतिकि तिब्बत कभी चीन से स्वतंत्र था। 6 दूसरी ओर भारत के लिए , मैकमोहन रेखा चीन के साथ 'वास्तविक' सीमा बनी हुई है। 7 भारतीय क्षेत्र पर चीन का दावा, और वास्तव में, चीन का सैन्य दबाव भारत तिब्बत पर अपने प्रत्यक्ष सैन्य कब्जे के कारण है। भारत के प्रति चीनी क और जटिलता की कमी तवांग पर अपने तिब्बती संबंधों के कारण और इस तथ्य के कारण परिलक्षित होती है कि पहले के दलाई लामाओं में से एक, एक संस्था जिसे उन्होंने राजनीतिक रूप से नष्ट करने की कोशिश की है, के विनाश का उल्लेख नहीं है।सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लामावादी आदेश और बौद्ध मठों का जन्म वहीं हुआ था। (एयू: क्या चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज संदर्भ में लेख का शीर्षक है?) चीनी अनाया सही भारत के खिलाफ तिब्बती कार्ड खेलते हैं। फिर भी यह चीन के खिलाफ तिब्बती कार्ड खेलने के लिए अनिच्छुक है। मूल रूप से, भारत और चीन के बीच तीन मुद्दों से संचालित एक जटिल संबंध है: हिमालय पर क्षेत्रीय विवाद, गहरी राष्ट्रवादी नाराजगी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता का मुद्दा भी इस विभाजन की ओर ले जाता है। न तो भारत और न ही चीन अपनी जमीन देने की मिसाल कायम कर सकता है।

चीन का सैन्य आधुनिकीकरण :

चीन साल दर साल आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत होता जा रहा है। इसके आकार को देखते हुए, ऐतिहासिक दृष्टि से इसके अपने दृष्टिकोण, भारत पर इसके दावे, ताइवान पर, दक्षिण चीन सागर आदि में, इसके उदय का इस क्षेत्र और उससे आगे के लिए निहितार्थ है।चीन का सैन्य आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण, तिब्बत में बुनियादी ढांचे का विकास और हिंदमहासागर में घुसपैठ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते पद चिह्न और परिधीय राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास केवल इन चिंताओं को जोड़ता है।चीन की अपारदर्शी राजनीतिक प्रणाली चिंताओं को जोड़ती है क्योंकि यह अपने आचरण कोअ प्रत्याशित बना देती है। 9 चीन का सैन्य बजट पिछले दो दशकों में दोहरे अंकों के आंकड़ों से बढ़ा है, वर्तमान 2012-13 के वित्तीय वर्ष परिव्यय 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। (एयू: कृपया इस डेटा को अपडेट करें।) यह प्रवृत्ति लगातार इस आशंका और चिंता को बढ़ावा देर ही है कि चीन एशिया और उसके बाहर एक तेजी से मुखर भूमिका निभाएगा।भारत में एक आम समझ है कि चीन की सैन्य आधुनिकी करण और भव्य रणनीति का मुख्य फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, विशेष रूप से एशिया-प्रशांत के लिए वाशिंगटन की हाल ही में घोषित 'पुनर्संतुलन रणनीति' के आलोक में ।भारत की चिंता

हालाँकि, PLA का आधुनिकी करण, मुख्य रूप से रॉबर्ट का पलान के अनुसार 'सैन्य प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण हुई दूरी के पतन' से उत्पन्न होता है, जिससे देशों को एक-दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने की अनुमति मिलती है।चीन के रक्षा खर्च में वृद्धि भारत- विशिष्टन हीं हो सकती है जैसा कि कुछ लोग तर्क देना चाहते हैं और यह कि वे पहले बताएगए इसके रणनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार हैं; हालाँकि, जिसे दूर नहीं किया जा सकता है वह रणनीतिक वास्तविकता है कि चीन की बढ़ती सैन्य प्रोफ़ाइल ने,प्रभाव के संदर्भ में, भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर रणनीतिक और सैन्य निहितार्थ पैदा किए हैं। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने आधुनिकी करण और गुणात्मक रूप से विस्तृत योजनाएँ तैयार की हैं। भारत के रणनीतिक हित के क्षेत्र में संचार और परियोजना शक्ति की समुद्री लेन को सुरक्षित करने की क्षमता सहित भविष्य की लड़ाई के लिए उनकी क्षमताओं का उन्नयन,पर्याप्त धन की कमी, देरी से निर्णय लेने और कम तकनीक के कारण आधुनिकी करण की गतिधीमी रही है।रक्षा औद्योगिक आधार। भारत का रक्षा बजट वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम आंका गया है ।और व्यय का बड़ा हिस्सा राजस्व खाते पर है- यानी वेतन और भत्ते, राशन, ईंधन, तेलऔरस्नेहक, गोलाबारूद, और वाहन। पूंजी खाते में आधुनिकी करण पर खर्च करने के लिए बहुत कमराशि बची है।सेना के मामले में,आधुनिकी करण पर खर्च 2012-13 में कुल पूंजीगत व्यय का 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत जितना कम है।पी एल ए आधुनिकी करण की तीव्र दर को देखते हुए, चीन के साथ अंतर, जो वर्तमान में केवल एक मात्रात्मक अंतर है, जल्द ही एक गुणात्मक अंतर बन जाएगा ।इसी तरह,पारंपरिक संघर्ष में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों पर अब भारतीय सशस्त्रबलों का जो पतला प्रभाव है,वह कम हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथी उग्रवाद से लड़ने की आड़ में अपने सैन्य आधुनिकी करण पर काफी पैसा खर्च कर रहा है।

मोतियों की माला:

एक 'मोती' को आर्थिक, भू-राजनीतिक, कूट नीतिक या सैन्य साधनों के उपयोग के माध्यम से बीजित, सुरक्षित और बनाए रखने वाले प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। 'मोतियों की माला' चीन की स्पष्ट समुद्री रणनीति के बारे में है जो अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने में निवेश करता है। यह अनिवार्य रूप से एक बहु-आयामी रणनीति है जो चुनौती देती है.

हिंदमहासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख हित हैं और चीन पर इस क्षेत्र में तटीय राज्यों की निर्भरता को बढ़ाकर एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि हिंद महा सागर भारत का महासागर नहीं है। वर्षों से चीन इस क्षेत्र के देशों को रणनीतिक समुद्री केंद्र विकसित करने में मदद कर रहा है। इसने विभिन्न राज्यों को नई समुद्री सुविधाएं बनाने या उनकी मौजूदा समुद्री संपत्तियों में सुधार करने में सहायता की है। चीन विभिन्न नौ वहन सुविधाओं को विकसित करने,गहरे पानी के बंदरगाहों और नौ सैनिक अड्डों के निर्माण,पाइपलाइन परियोजनाओं के विकास और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तंत्रस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।ऐसा करके , यह भारत के पड़ोस में क्षेत्र के विभिन्न देशों को जोड़ने में

सफल रहा है। 13 परिवहन के रणनीतिक क्षेत्र पर चीन का ध्यान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान में देखा जा सकता है। इसके अलावा, अरुणाचलप्रदेश जैसे भारत के कुछ हिस्सों पर इसके क्षेत्रीय दावे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन की कमी, सभी एक क्षेत्रीय के रूप में भारत के उदय को रोकने के चीन के प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। और वैश्विक खिलाड़ी ।चीन ने लगातार यही रणनीति अपनाई है।वास्तव में,यह रणनीति इतनी सफल रही है कि कुछ पर्यवेक्षकों को लगता है कि भारत चीन के कूटनीति कर डर से दूर है। 14.

चीन और बांग्लादेश:

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने कुछ भारतीय नीति निर्माताओं को चिंता में डाल दिया है,वह बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दिल चस्पी है।चीन और बांग्लादेश पुराने मित्र हैं।हालाँकि, हाल के वर्षों में,ढाका-बीजिंग संबंधन ई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं क्यों कि चीन भारत की जगह बांग्लादेश का नंबर एक व्यापारिक भागीदार बन गया है, और बांग्लादेश में चीनी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।इसके अलावा, बीजिंग बांग्लादेश के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, पहले से ही छह मैत्री पुलों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करा चुका है।बांग्लादेश में चीन के आर्थिक और सामरिक दोनों हित हैं ।जब कोई सुरक्षा सहयोग को देखता है तो चीन और बांग्लादेश के बीच संबंध और भी व्यापक होते हैं। बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को सैन्य हार्डवेयर और प्रशिक्षण का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के नाते, बीजिंग ढाका के सुरक्षातंत्र को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाताहै। दरअसल, 2002 में, बांग्लादेश ने चीन के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो बांग्लादेश द्वारा अपने इतिहास में अब तक का पहला समझौता है।

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन का दौरा किया और चीनी प्रधानमंत्री वेनजियाबाउ और राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में,चीन बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्विपक्षीय व्यापार उच्च स्तर पर बढ़ रहा है लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को अधिसूचित किया जाना चाहिए। वास्तव में, चीन विभिन्न परियोजनाओं, सहायता,निवेश, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने में बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है।चीन ने बांग्लादेशी चट गाँव बंदरगाह तक नौ सेना की पहुँच प्राप्त कर ली है, जो चीन को म्यांमार के तेल क्षेत्रों और भारत के आसपास के समुद्रों के करीब लाने में मदद कर सकता है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में चीनी नौ सैनिक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है।चीन के सक्रिय सहयोग से, बांग्लादेश ने (एयू: वाज़दिसइन 2015?) चीन की जमीन पर हमला करने वाली एंटी-शिप क्रूज मिसाइल सी-802 एका अपना पहला मिसाइल प्रक्षेपण जियांघू-श्रेणी के 1,500-टन एफ-18 उस्मान फ्रिगेट से किया। पिछले साल बंगाल बांग्लादेश में चटगांव नौ सैनिक बंदरगाह के आधुनिकी करण के साथ, चीन बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौ सेना के आंदोलन को रोकने का इरादा रखता है।चीन-पाकिस्तान गठजोड़चीन-पाकिस्तान गठजोड़ अगला प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दा है। इस खाते पर भारत की संवेदनशीलता के बारे में चीन में बेहतर समझ की आवश्यकता है। पाकिस्तान को चीनी सेना, मिसाइल और परमाणु मदद जारी है, लेकिन बीजिंग भारत को यह गारंटी देने की स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ने के लिए चीन से इस तरह के समर्थन का लाभ नहीं उठाएगा। आश्चर्य नहीं कि नई दिल्ली यह मानती है कि पाकिस्तान को चीन की सैन्य सहायता का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 17 (एयू: कृपया फुट नोट में लेखक का नाम और लेख का शीर्षक प्रदान करें।) भारत के साथ अपने संघर्ष में पाकिस्तान के लिए चीन का समर्थन, चीन-भारतीय संबंधों में तनाव का एक गंभीर और जारी स्रोत है, जब कि पाकिस्तान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध भी तेजी से भया वह दिख रहे हैं। 2008 के असैन्य परमाणु समझौते के मद्दे नजर भारत के साथ इसके संबंध में सुधार हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के संबंध उनके पारस्परिक हितों के अभिसरण पर आधारित हैं। चीन भारत को संतुलित करना चाहता है और पाकिस्तान हमेशा एक राजनीतिक ढाल चाहता है। हालाँकि चीन दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पाकिस्तान बना रहे.

भारत के लिए एक मजबूत सैन्य प्रतिकार। बीजिंग-इस्लामाबाद 'विशेष संबंध' चीन की भव्य रणनीतिक हिस्सा है जो एशियाई सुरक्षा वातावरण को ढालता है।

चीन -पाकिस्तान सैन्य गठबंधन (विशेष रूप से, परमाणु और मिसाइल गठजोड़) यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति का दक्षिण एशियाई सैन्य संतुलनन तो भारत समर्थक है और नही पाकिस्तान समर्थक है, बल्कि चीन समर्थक बना हुआ है ।बीजिंग भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति इस्लामाबाद के गहरे अविश्वास को साझा करता है और भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखता है जिसे संतुलित होना चाहिए।चीनियों का मानना है कि जबतक भारतीय सेना अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ व्यस्त है, नई दिल्ली चीन और पूर्वी एशिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती ।बीजिंग ठीक ही गणना करता है कि यह दिन दिल्ली उपमहाद्वीप को प्रभावित नहीं कर सकती है, तो बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव मूक हो जाता है। चीन की घरेलू और बाहरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को चीनी समर्थन को भी समझने की जरूरत है। 18 चीन और नेपाल नेपाल में चीन की सुरक्षा और विदेश नीति के उद्देश्य कई हैं।वस्तुतः इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। (एयू: दोहराया गया।नीचे देखें।) नेपाल और चीन एक लंबी सीमा साझा करते हैं, जो लगभग 1,414 किलोमीटर तक फैली हुई है। चीन नेपाली राजनीति के भविष्य के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।19 नेपाल चीन की दक्षिण एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है ।माओत्सेतुंग की पांच अंगुलियों की नीति को याद किया जा सकता है जिसमें नेपाल ने लद्दाख, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ पांच अंगुलियों में से एकका गठन किया था। 1951 में 'ओल्डबफर' (तिब्बत) के चीन के सार्वभौम नियंत्रण में आने के बाद पांच अंगुलियां अनिवार्य रूप से भारत और चीन के बीच एक 'न एबफर' क्षेत्र के रूप में काम करने के लिएथीं।नेपाल भारत के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। ए 1950 के दशक तक चीन की नेपाल में सबसे कम दिल चस्पी थी। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर बल पूर्वक कब्जा कर लिया तो रणनीतिक डिजाइन बदल गया। तिब्बत में बढ़ते तनाव के साथ, विशेष रूप से मार्च 2008 के विद्रोह के बाद, एक नए बफर के रूप में नेपाल की चीन की अवधारणा ने विशेष महत्व हासिल कर लिया। नेपाल के प्रति इसकी नीतिने पाल में करीब 20,000 तिब्बती शरणार्थियों (दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती शरणार्थी समुदाय) की गुप्त गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता से प्रेरित थी।नतीज तन, नेपाली राजनीति के भविष्य के आकार को निर्धारित करने में चीन तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उच्चस्तरीय बैठकों में से प्रत्येक के दौरान चीन ने नेपाल से आश्वासन निकाला है कि वह एक- चीन सिद्धांत का पालन करता है, तिब्बत को चीन के एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करता है, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी धरती पर चीन विरोधी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

चीन की दक्षिण एशिया नीति में रेखांकित नेपाल में भारत के प्रभाव को हाशिये पर डालने की रणनीति है। भारत को हाशिए पर डालने से चीन को न केवल दक्षिण एशिया पर हावी होने की अनुमति मिलेगी,बल्कि नेपाल की लगभग 83,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता तक आसान पहुंच भी उपलब्ध होगी ।20 दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत होना काफी स्वाभाविक है। लेकिन नेपाल में चीन के अतिक्रमण का भारत की हिमालयी सुरक्षा पर वास्तविक और ठोस सामरिक प्रभाव पड़ा है। भारत में अधिकांश आतंकवाद और उग्रवाद संबंधी समस्याओं का सीमा-पार संबंध है।नतीज तन,सीमा प्रबंधन भारत के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बन गया है। नेपाल में निरंतर अस्थिरता और नेपाल के साथ चीन की बढ़ती निकटता के कारण भारत-नेपाल सीमा हाल के वर्षों में ही महत्वपूर्ण हो गई है। 21 चीन और म्यांमार म्यांमार खुद को दो एशियाई दिग्गजों-चीन और भारत के बीच 'सैंडविच' महसूस करता है। भारत के दृष्टिकोण से, म्यांमार उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं, स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्वका तत्काल पड़ोसी है, और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभावका विस्तार है। म्यांमार वह जगह नहीं है जहां केवल चीन और भारत 'मिलते' हैं; यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच का चौराहा भी है। इस प्रकार, कनेक्टिविटी और सहकारी लिंक के विस्तार के माध्यम से म्यांमार को भारत और आसियान और उससे आगे के बीच 'गेटवे' के रूप में मानने में दोनों देशों का रणनीतिक अभिसरण है। 22 आर्थिक रूप से, म्यांमार हिंद महासागर के व्यापारिक आउट लेट के रूप में

चीन के लिए महत्वपूर्ण है।युन्नान और सिचुआन के इसके लैंडलॉक अंतर्देशीय प्रांत। रणनीतिक रूप से, म्यांमार चीन के लिए हिंदमहासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और इसके दीर्घ कालिक दो-महासागर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण है ।इसके अलावा, चीन-म्यांमार गठजोड़ दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए चीन के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी है। अंत में, म्यांमार इक्कीसवीं सदी में एक महान शक्ति बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीन के भव्य रणनीतिक डिजाइन का हिस्सा और पार्सल है। 23 भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता म्यांमार के ऊर्जा संसाधनों की खोज के अधिकार और पहुंच को लेकर भी उभरी है। चीनी कंपनियों ने हमेशा म्यांमार में अपने मजबूत प्रभाव के माध्यम से या भारत की कमजोरियों का फायदा उठाकर अनुबंधों का एक बड़ा हिस्सा हड़पने में कामयाबी हासिल की है। तबसे 1980 के दशक केउत्तरार्ध में, चीन ने म्यांमार को बहुत अधिक रक्षा सहायता प्रदान की है। इसने म्यांमार के तट और को को द्वीप समूह में नौ सैनिक सुविधाओं, रडार और सिग्नल- इंटेलिजेंस (SIGINT) चौकियों का निर्माण किया है, जो भारत के अंडमान द्वीप समूह से बमुश्किल 18 किमी उत्तर में स्थित है।म्यांमार की नौ सैनिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए चीनी समर्थन से भारत विशेष रूप से चिंतित है। मई 1998 में, मुखर भारतीय रक्षामंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस ने बीजिंग पर म्यांमार को कोको द्वीप, म्यांमार में निगरानी और संचार उपकरण स्थापित करने में मदद करने का आरोप लगा कर हंगामा खड़ा कर दिया और चीन ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन नई दिल्ली की चिंताएँ अच्छी तरह से स्थापितथीं। पिछले साल (एयू: 2015?) भारतीय नौ सेना ने म्यांमार में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में एक नएसुदूर पूर्वी नौ सेना कमान की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, चीनम्यांमार (हंगयी) में बंदरगाह सुविधाओं के विकास में भी शामिल है।), श्रीलंका (हंबनटोटा), मालदीव और पाकिस्तान में ग्वादर को कई भारतीय विश्लेषकों द्वारा उत्तरी हिंदमहासागर क्षेत्र पर हावी होने के लिए 'मोतियों की माला' रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसलिए, इन कदमों को एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए दीर्घा वधि में भारत को रणनीतिक रूप से घेरने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना का हिस्सा माना जाता है। चीन और श्री लंका पिछले कुछ वर्षों के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। श्रीलंका ने हंबनटोटा में एक बंदरगाह के निर्माण में चीनी निवेश, अपने गृह युद्ध में उपयोग के लिए चीन से हथियार और शंघाई सहयोग संगठन में 'संवादभागीदार' की स्थिति का स्वागत किया। इस तरह के हाईप्रोफाइल कदमों ने हिंदमहासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बढ़ने के डर से विश्लेषकों को बेचैन कर दिया है।चीन के साथ श्रीलंका के आर्थिक, सैन्य और राजनयिक संबंधों के रुझानों के पहली बार व्यवस्थित

विश्लेषण से पता चलता है कि संबंध वास्तव में मजबूत हो रहे हैं।लिबरे शन टाइगर्स ऑफ तमिलईलम (एलटीटीई) के खिलाफ श्री लंकाई सरकार के समर्थन की चीन की घोषणा, दुनिया की आंखों में गले के अंगूठे की तरह दिखने के अलावा, अपने सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पड़ोसी के प्रतिभार तकेनश्वरअ विश्वास को और बढ़ा दिया है। जबकि भारत की अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण इस मुद्दे पर अधिक सूक्ष्म स्थिति है, एक खुला चीन को लंबो का समर्थन कर रहा है और इस प्रक्रिया में, बीजिंग के अपने प्रभाव को बढ़ाने के बारे में भारत के डर को प्रमाणित कर रहा है।

38 • समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ: हिंदमहासागर में बदलता परिदृश्य ।सरकारी सूत्रों के अनुसार, को लंबो को बीजिंग के समर्थन को अलग कर के नहीं देखा जा सकता है क्यों कि यह श्रीलंकाई सरकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से कई पहलों का अनुसरण करता है।इनमें पिछले साल को लंबो को भारी मात्रा में हथियार बेचना (एयू: 2015 में?) और सहायता को लगभग पांच गुना बढ़ाकर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना शामिल है। वास्तव में, चीन अब लंका का सबसे बड़ा दान दाता है। इसके जियान-7 फाइटर जेट्स, एंटी-एयरक्राफ्टगन और JY-11 3डी एयर सर्विलांस राडार ने श्रीलंकाई सैन्य सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।25 दक्षिण चीन सागर एशिया सहित भारत-चीन समुद्री प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से समुद्री-कॉन्फ़िगर क्षेत्र है। हिंदमहासागर और इसके तट पर स्थित राज्य महत्वपूर्ण और बढ़ते महत्वके हैं। इस क्षेत्र में दुनिया की आबादी का एक तिहाई, इसके भूभाग का 25 प्रतिशत और दुनिया के तेल और गैसभंडार का 40 प्रतिशत हिस्सा है। यह संचार की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखाओं (SLOCs) का ठिकाना है। हिंद महासागर दुनिया के दो सबसे नए परमाणु

हथियार वाले राज्यों, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ ईरान का भी घर है, जो कि अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि परमाणु हथियार हासिल करने के लिए एक मजबूत कार्यक्रम है।हिंदमहासागर में चीन की अत्यधिक रणनीतिक अनिवार्यता अपने एसएलओसी की रक्षा करना है, विशेष रूप से मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से चीन को परिवहन ऊर्जा। चीन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसके एसएलओसी राज्य और गैर- राज्य अभिनेताओं के खतरों के प्रतिसंवेदन शील हैं। यह फारस की खाड़ी में एक 'हो र्मुज दुविधा' का सामना करता है, जहां चीन के तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हॉर्मुजजलडमरूम ध्य से होकर जाता है। मलक्काज लड मरू मध्य में चीन और भी अधिक असुरक्षित है, जिसके माध्यम से चीन का लगभग 82 प्रतिशत तेल आयात होता है। हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत चीन पर स्पष्ट सैन्य लाभ रखता है। पूर्वभारतीय नौसेनाध्यक्ष एडमिरल मेहता ने टिप्पणी की: 'चीन के लिए आज कमजोर क्षेत्र भारतीय नौ सेना है। हम हिंदमहासागर में बैठते हैं और यह चीन के लिए चिंता का विषय है और वे खुश नहीं हैं क्यों उनके लिए अंदर आना इतना आसान नहीं है। '26 इस प्रकार भारत-चीन की अधिकांश बातचीत समुद्रया तटीय क्षेत्रों से संबंधित होगी ।यद्यपि दोनों देश एक समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं,लेकिन उभरती हुई शक्तियों के रूप में , उनके महत्वपूर्ण सुरक्षाहित उनकी तत्काल परिधि से लेकर क्षेत्रीय चरम सीमाओं तक फैले हुए हैं ।दूसरे शब्दों में, जबकि उनकी तत्काल सुरक्षा अनिवार्यता एंपश्चिमी प्रशांतमहासागर में हैं और हिंदमहासागर, क्रमशः; उन करण नीतिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में ओवर लैप होने लगे हैं।यह उन्हें पूरे एशियाई क्षेत्र में अपने समुद्री रणनीतिक 'पदचिह्न' को फैलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए,इसके प्रभावों को दक्षिण-पूर्व एशियाके भू-सामरिक उप-क्षेत्र में महसूस किया जाना तर्क संगत है, जो उत्तर-पश्चिमी प्रशांतमहासागर से लेकर अरबसागर तक फैले 'भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता चक्र' के मध्य में स्थित है। इसलिए, भारत के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास निर्माण के लिए दक्षिण-पूर्वएशिया (इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार) के अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ अपने नौ सैनिक जुड़ाव को बढ़ाए। अप्रैल 2008 में, भारत और म्यांमार ने कलादान नदी परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह का उन्नयन शामिल है। इसने दावेई में एक गहरे पानी के बंदरगाह के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है ।27 दक्षिण चीन सागर में समुद्री लेन को खुला रखने में भारत की गहरी दिल चस्पी है।दक्षिण चीन सागर न केवल प्रशांत और हिंदमहासागर के बीच एक रणनीतिक समुद्री संपर्क है, बल्कि पूर्वी एशिया में नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है।एशिया प्रशांत के साथ भारत का लगभग 55 प्रतिशत व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होता है।जापानऔरकोरियाजैसे देशों के लिए सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति में मदद करने के अलावा, भारत को क्षेत्र के समुद्री मार्गों के माध्यम से सखा लिनसेमैंग लोर तक तेल भेजने का अनूठा गौरव प्राप्त है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत और चीन के बीच एक साल से अधिक समय से तनातनी चल रही है।भारत ने दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज का विस्तार और बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2011 में वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्लॉक 127 और 128 में तेल और गैस का पता लगाने के लि एवियत नामी निमंत्रण को स्वीकार कर के, भारत की राज्के स्वामित्व वाली तेल कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एनजीसी विदेश लिमिटेडया ओ वी एल) नेनकेवल वियत नाम के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करने की नई दिल्ली की इच्छा व्यक्त की। लेकिन चीन की दूर रहने की चेतावनी को नजर अंदाज करें। "क्षेत्र के बाहर" के देशों को दक्षिण चीनसागर से दूर रहने के लिए कहने के बाद, चीन ने नवंबर 2011 में भारत को एक डिमार्श जारी किया, जिस में रेखांकित किया गया कि ब्लॉक 127 और 128 में अन्वेषण के लिए बीजिंग की अनुमति मांगी जानी चाहिए और इसके बिना, ओ वी एल की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। अवैध माना।इस बीच, वियतनामने समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रेखांकित किया था ता कि खोजे जा रहे दो ब्लॉकों पर अपने संप्रभुअधिकारों का दावा किया जा सके ।वियतनाम के ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच में भारत की रुचि इसे क्षेत्र पर चीन के दावों के साथ सीधे संघर्ष में डालती है। वस्तुत : यह मुद्दा केवल वाणिज्य और ऊर्जा का ही नहीं है बल्कि यह भी है. एशियाई परिदृश्य में दो उभरती शक्तियों के बीच सामरिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में। यदि चीन हिंदमहासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर सकता है, जैसा कि नई दिल्ली ने अनुमान लगाया है, तो भारत दक्षिण चीन सागर के जल

में भी ऐसा ही कर सकता है। 28 इसलिए, भारत के लिए इस क्षेत्र तक पहुंच बनाना महत्वपूर्ण है।अगर चीन इन जल क्षेत्रों पर प्रभुत्वज ताना जारी रखता है, तो भारत के लिए इस माध्यम से अपनी गतिविधियों को जारी रखना मुश्किल होगा ।दक्षिण चीन सागर पर चीन की सख्त लाइन का असर भारत पर भी पड़ा है। इस क्षेत्र में तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक भारतीय कंपनी द्वारा बीजिंग की योजनाओं की निंदा करने के बाद भारत थोड़ा अचंभित हो गया।चीनी आपत्तिओ एन जी सी विदेश के वियतनाम (चीन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं) से संबंधित पानी में अपतटीय तेल अन्वेषण के उद्यम पर थी, बीजिं गने भारत से विवादित एससी एस में तेल और गैस की खोज करने वाली वियतनामी फर्मों के साथ सौदे करने से बचने का आग्रह किया (एयू: कृपया विस्तार करें।) जिस पर चीन को 'निर्विवाद' संप्रभुता प्राप्त है। 29 चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में स्तंभका रलियूशेंग का एक हालिया लेख दक्षिणचीन सागर में तेल और गैस की खोज के लिए वियतनाम के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ भारत को आगाह करता है, यह एक समयोचित कदम है। चीन-भारतीय संबंधों में अभी भी मौजूद खतरनाक नुकसान की याद दिलाता है। ग्लोबलटाइम्स ने चीन के विदेशमंत्रालय के एक प्रवक्ताजियांग यूके हवाले से कहा कि: 'जहां तक तेल और गैस की खोज की बात है... हम चीन के अधिकार क्षेत्र के तहत जल में लगे किसी भी देश के खिलाफ हैं। हमें उम्मीद है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में अन्य देश शामिल नहीं होंगे। हालांकि सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया गया, फिर भी उंगली साफ तौर पर भारत की ओर उठी। ओ एन जी सी का वियतनाम में लगभग 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है। 30 दबाव में आकर, ओएनजीसीने पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर ब्लॉक छोड़ने का इरादा व्यक्त किया है।हालांकि इसका कारण बताया गया है कि इस ब्लॉक में कुएं खोदने के बार-बार के प्रयासों के बावजूद ब्लॉक में कठोर समुद्री तल के कारण विफल रहे हैं, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा: 'यदि ओ एन जी सी ब्लॉक 128 से बाहर निकलती है, तो भारत को इसके आगे झुकते हुए देखा जा सकता है । बीजिंग का दबाव जो भारत द्वारा अन्वेषण गतिविधियों को अवैध करार देता रहा है।' 31 इसके अलावा, भारत के परमाणु हथियार कार्य क्रम का चीन का विरोध; म्यांमार में उसके सैन्य शासन को उसका समर्थन और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती गतिविधियाँ; आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) में भारत को अलग-थलग करने के इसके प्रयास; और,नेपाल,भूटान और बांग्ला देश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इसके अथक प्रयास। (एयू: वाक्य अधूरा है। कृपया पुन: जांच करें।) चीन की अच्छी तरह से निर्धारित नीति के विपरीत, भारत समय-समय पर एक अति से दूसरी अति पर झूलता रहा है। जॉर्ज तन हमने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक रूप से सोचने की कम क्षमता दिखाई है। भारत की चीन नीति के मामले में, यह महसूस करने की आवश्यकता है कि चीन के अपने प्रभाव को बढ़ाने और भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों के बारे में वास्तव में कुछ भी भयावह नहीं है।चीन एशिया और दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति है और इसलिए वह भारत की तरह अपनी परिधि के आसपास अन्य शक्ति केंद्रों के उदय को रोकने की पूरी कोशिश करेगा जो भविष्य में इसे एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपना सही स्थान लेने से रोक सकता है। भारत दोनों और आसियान देश दक्षिण- पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीनी इरादों, रणनीतियों और आंदोलनों के बारे में आशंकित महसूस करते हैं। क्षेत्र की एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में खुद को चीन द्वारा पेश किए जाने के न केवल भारत बल्कि आसियान देशों के लिए भी गंभीर प्रभाव हैं। सोवियत संघ के विघटन और एक नई विश्व व्यवस्था के उद्भव ने उनकी सुरक्षा और आर्थिक विकास के संदर्भ में इस चुनौती को और तेज कर दिया है। आसियान देश अपनी समुद्री सीमाओं और 200 मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पार्टलेज़ द्वीप समूह, म्यांमार और दक्षिण चीनसागर क्षेत्रों को चीन द्वारा अपने रणनीतिक विस्तार के रूप में पेश किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, वे बेहतर सुरक्षा वातावरण के तरीके और साधन विकसित करने के लिए अधिक सहयोग और परामर्श का भी आह्वान करते हैं। भारत ने अपनी ओर से आसियान देशों को प्रसन्न रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक बात चीत के प्रस्तावों को सामने रखा है,जिसमें आसियान देशों की नीतियों और धारणाओं के अनुरूप हिंदमहासागर में संयुक्त भारत-अमेरिकी नौ सैनिक अभ्यास शामिल हैं। वर्तमान और भविष्यवादी रुझान वर्तमान में, भारत और चीन दोनों वैश्विक ऊर्जा मिश्रण,जलवायु परिवर्तन,हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, गैर-

पारंपरिक सुरक्षा खतरों,आतंकवाद,विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यू एम डी, मानवाधिकारों और दक्षिण के विविधी करण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं। -दक्षिण सहयोग. द्विपक्षीय रूप से, दोनों पक्षों का लक्ष्य अब 'समानता पर आधारित मित्रता और विश्वास क रिश्ता बनाना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चिंताओं के प्रतिसंवेदनशील हो और दूसरे की आकांक्षा'.33 (एयू: किसका उद्धरण फुट नोट में उल्लिखित है? कृपया फुट नोट में पूरा विवरण दें।) अप्रैल 2011 में, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सान्या, हैनान, चीन में आयोजित किया गया था।आयोजन के दौरान, भारत और चीन दोनों रक्षा सहयोग बहाल करने पर सहमत हुए , और चीन ने संकेत दिया था कि वह जम्मू और कश्मीर के निवासियों को नत्थी वीजा देने की अपनी नीति को उलट सकता है। इस अभ्यास को बाद में बंद कर दिया गया था,और इसके परिणाम स्वरूप,दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध फिर से शुरू हो गए थे और संयुक्त सैन्य अभ्यास की उम्मीद की जा रही थी। 34 चीन को पाकिस्तान पर अपने लाभ का उपयोग कर के पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने के रूप में भी देखा जाता है। 35 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक अन्य क्षेत्र है जिसमें चीन और भारत पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों देश अपनी सीमाओं के पार से उभरने वाले पैन-इस्लामिक कट्टर पंथी आतंकवाद के शिकार हैं। एक जिम्मेदार क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में खुद को पेश करने के चीन के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, कुछ लोगों द्वारा चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ सहयोग कर के दक्षिण एशिया में शांति और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समर्थन के रूप में देखा जाता है। वैश्विक आकांक्षाओं और कुछ महत्वपूर्ण परस्पर विरोधी हितों के साथ भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। नतीज तन, उनके द्विपक्षीय संबंधों में कुछ हद तक घर्षण अपरिहार्य है ।भारत एशिया में एक उभरती हुई शक्ति है और इसे अंतरराज्यीय पदानुक्रम में अपनी उचित जगह की मांग करने की आवश्यकता है। लेकिन उसे वह सम्मान तभी मिलेगा जब वह किसी प्रमुख एशियाई शक्ति के लिए उपयुक्त तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे।यदि भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की अपनी इच्छा को लेकर गंभीर है, तो उसे चीन के उदय की चुनौती से निपटना होगा। एक उभरता हुआ चीन एक उभरते हुए भारत को अपने समकक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां तक कि अगर उभरते हुए भारत का क्षेत्रीय आधिपत्य बनने का कोई इरादा नहीं है, तो भी चीन भारत को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि वह पहले ही काफी हद तक कर चुका है।और यह वह नियंत्रण है जिससे भारत को बचना है। जहां तक भारत की चीन नीतिका संबंध है, आधिकारिक स्थिति में निरंतरता दिखाई देर ही है और चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और बातचीत के माध्यम से चीन-भारत के मतभेदों को हल करने के लिए भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम में आम सहमति है। चीन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत चीन का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागी दार है। 2011में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 74 बिलियनअमेरि की डॉलर पर पहुंच गया।(एयू: कृपया इस डेटा को अपडेट करें।) दोनों देशों ने 2015 तक अपने व्यापार की मात्रा को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। अपडेट।) आपसी आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है

तेजी से और द्विपक्षीय व्यापार इस साल 40 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। हालाँकि, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधगति बनाए रखने में विफल रहे हैं। भारत को तिब्बत के प्रति चीनी संवेदन शीलता के प्रतिसंवेदनशील होने की आवश्यकता है क्यों कि यह चीनी पक्ष को अपने हितों को संप्रेषित करने में एक मुखर भूमिका निभाने में विफल रहा है।दूसरी ओर,चीन ने भारत-तिब्बत सीमा पर बेहतर नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। भारत की रक्षा तैयारी,चीन की तुलना में वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है जैसा कि भारत के पूर्व सेना प्रमुखों में से एक ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ दो-फ्रंट युद्ध परिदृश्य की संभावना को सिद्धांत तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।युद्ध और परिचालन की तैयारी। इस एशियाई सदी का भविष्य काफी हद तक दो क्षेत्रीय दिग्गजों के बीच संबंधों पर निर्भर करेगा। उभरती हुई वैश्विक प्रवृत्तियों पर यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 तक, (AU: 2016 के बारे में क्या?) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन और भारत के उदय के सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक आयामों का सामना करना होगा। 36 पांचवें में भारत-चीन सामरिक वार्ता,सीमा पार नदी के पानी के उपयोग पर

समझ बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने, भारत द्वारा सामना की जाने वाली बड़ी और बढ़ती घाटे की समस्याओं को दूर करने, लाइन के साथ शांति और शांति बनाए रखने के तरीकों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत-चीन सीमाक्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण (एलएसी), सहयोग बढ़ाने के तरीकों के साथ-साथ वैज्ञानिक और तकनी की सहयोग का आदान-प्रदान और विस्तार ।37 चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध एशिया में नए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे की रूप रेखा को परिभाषित करेंगे और दुनिया बड़े पैमाने पर। आज की स्थिति में, पिछले कुछ वर्षों में कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक विकासों के बावजूद भारत-चीन संबंधों की गति हमेशा की तरह जटिल बनी हुई है। इसलिए, भारत और चीन दोनों को इस शांति और स्थिरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बाहरी हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। सह स्राब्दी के मोड़ पर, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक परस्पर निर्भरता के माध्यम से दुनिया बदल रही है, दोनों देशों के नेतृत्व को अपने लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विश्वास निर्माण उपायों, प्राचीन विवादों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने, बल द्वारा संघर्ष समाधान के बजाय आम सहमति तक पहुंचने के माध्यम से पड़ोसियों को उनके हितों को आश्वस्त करने की आवश्यकता आजकी आवश्यकता है।शीत युद्ध के बाद की वास्तविकता एक विश्व व्यवस्था की है

राज्यों के बीच इक्विटी और व्यापार और आर्थिक विकास के माध्यम से रचनात्मक जुड़ाव पर आधारित है। यहां तक कि कुछ आधिपत्य और अन्य समान मानसिकताओं को अभी भी देखा जाना बाकी है, अंतर-राज्य संबंधों का भविष्य सहयोग के रास्ते पर अच्छी तरह से स्थापित है। इसलिए, भारत और चीन दोनों को सहयोग की आवश्यकता और आपसी समझौतों के माध्यम से पुरानी दुश्मनी से दूर जाने की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। सन्दर्भ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. कंवलसिब्बल, 'भारत-चीनसंबंध: कुछ प्रतिबिंब', भारतीय रक्षा समीक्षा, खंड। 23, नंबर 1, जनवरी-मार्च 2008।जवाहर लाल नेहरू (एसडब्ल्यूजेएन) के चयनित कार्य, श्रृंखलाII, वॉल्यूम। 14, नहीं। 1, नईदिल्ली, 1992, पृ. 516. हर्षवी. पंत, 'भारतीय विदेश नीति और चीन', सामरिक विश्लेषण, खंड। 30, नहीं। 4, अक्टूबर-दिसंबर। 2006, पृष्ठ 760। 'नोट्स, ज्ञापन और पत्रों का आदान-प्रदान और भारत और चीन की सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते', विदेश मंत्रालय, श्वेतपत्र 1, 1954-59, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, 1959।डी.एस. राजन, 'भारत-चीनसंबंध: एकइंडियनप र्सपेक्टिव', इकोनॉमिक ऑब्जर्वर, 29 जून 2010।झूहुआ, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिकस्टडीज, बीजिंग, 18 मार्च 2008। प्रणब मुखर्जी, न्यूजटुडे, चेन्नई, 4 जून 2008। उक्त। ऑप। सीआईटी। (3)। 10. रॉबर्टडी. कापलान, 'दइंडिया-चाइना राइवलरी', स्ट्रैटफोर, ग्लोबलइंटेलिजेंस, 25 अप्रैल 2012। 11. सुभाषकपिला, 'चीन का बढ़ा हुआ रक्षा बजट और भारत के लिए इसका प्रभाव-विश्लेषण', 8 फरवरी 2014; http://www.eurasiareview पर उपलब्ध है।com/08022014-chinas-increased-defence-Budget-implications-india-analysis/ (पर देखा गया)। 12. लक्ष्मण के. बेहरा, 'भारत का रक्षाबजट 2012-13, आईडीएसएटिप्पणी, 20 मार्च 2012; http://www.idsa.in/idsacomments/ IndiasDefenceBudget2012-13_LaxmanBehera_200312 पर उपलब्ध है। 13. अजय लेले, 'चीन के "स्ट्रिंगऑफपर्ल्स" इनस्पेस', आईडीएसएकमेंट; http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/ChinasString%20of%20 PearlsinSpace_AjeyLele_210312 (परदेखागया) पर उपलब्ध है। 14. स्टीफन पी. को हेन, इंडिया: इमर्जिंग पावर, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, वाशिंगटन, डीसी, 2001, पी। 1. 15. एम. शाहिदुल इस्लाम, 'बांग्लादेश-चीन-पूर्वोत्तरभारत: अवसर और चिंताएं', आईएसएएसइनसाइट्स, नहीं। 36, 8 सितंबर 2008। 16. संजय कुमार, 'चीन की नौ सेना रणनीति: भारत के लिए निहितार्थ', 2 मार्च 2009; http://www.ipcs.org/article_details.php?articleNo=2823 पर उपलब्धहै। 17. news.outlook.India.com/item.aspx?662473 (पर देखागया)।

Nepal, South Asia Monitor'; available at www.southasiamonitor.org,/nepal/2006 (accessed on). 22. Rajiv Bhatia, 'India-Myanmar Relations: A Critical Review, Voice of India'; available at voice of.india.com/india-myanmar-relations-chats-with-ambassador (accessed on). 23. Poon Kim Shee, 'The Political Economy of China-Myanmar Relations: Strategic and Economic Dimensions', Ritsumeikan Annual Review of International Studies, vol.1, 2002, p. 33. 24. 'China's Ambitions in Myanmar: India Steps up Countermoves', Asia-Pacific Media Services Limited, available at

www.asiapacificms.com/articles/myanmarinfluence (accessed on). 25. Available at http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-04-26/ india/28028823_1_china-colombo-beijing (accessed on). 26. Available at http://indiatoday.intoday.in/story/indian-ocean-india-china-strategicrivalry-tensions/1/271324.html (accessed on). 27. 'Myanmar, India Finalizing River Transportation Project', Xinhua, 28 August 2007, FBIS/ World News Connection; available at http://wnc.dialog.com/ (accessed on). 28. Harsh V. Pant, 'South China SEA: New Arena of Sino-Indian Rivalry', Yaleglobal, 2 August 2012; available at yaleglobal.yale.edu/.../south-china-sea-new-arenasino-indian-rivalry (accessed on). 29. Atam Singh, 'South China Sea Dispute and India'; available at http://maritimeindia. org/article/south-china-sea-dispute-and-india (accessed on). 30. R.S. Kalha, 'India and the South China Seas: The Need for a Second Look', IDSA Comment; available at http://www.idsa.in/idsacomments/ IndiaandtheSouthChinaSeasTheNeedforaSecondLook_rskalha_230911 (accessed on). 31. 'India One Step Back in South China Sea', Hindustan Times, 24 April 2012. 32. Harsh Pant, 'India's China Policy: Importance of a Strategic Framework'; available at http://www.bharat-rakshak.com/SRR/2005/03/30-indias-chinapolicy-importance-of-a-strategic-framework.html (accessed on). 33. 'A Shared Vision for the 21st Century of the PRC and India', Beijing, January 2008. 'The two sides remain firmly committed to resolving outstanding differences, including on the boundary question, through peaceful negotiations, while ensuring th[at] such differences are not allowed to affect the positive development of bilateral relations.' 34. 'Indian Military Review, 2012'; available at www.idyb.com/imr/home.php (accessed on). 35. 'China Pursues India-Pakistan Peace', Wall Street Journal, 8 December 2003. 36. Available at http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2015.html (accessed on). 37. 'The 5th India-China Strategic Dialogue', Strategic Digest, vol.43, no.9, Aug-Sep

Publish Research Article

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication.

Address:-Ashak Hussain Malik House No-221, Gangoo Pulwama - 192301 Jammu & Kashmir, India
Cell: 09086405302, 09906662570,
Ph No: 01933212815
Email: nairjc5@gmail.com
Website: www.nairjc.com